India, Bengal has some difficulties; rice yields are not at the desirable levels. He himself was good enough to point out about the availability of water; that is not being used in full and the infra-structure has not been fully developed; extension methods are not effective. But even in Bengal some areas the rice yields are quite high. That means that if the necessary inputs and supplies are there, one could expect better results. But because of the poverty of the farmers and the weakness of credit institutions we are not in a position to make inputs available to a large number of farmers in time and in sufficient quantities. These are some of the weakness and we are trying to remove them.

SHRI P R SHENOY: According to the recent Economic Survey published by the Government of India, though the area of production has been increasing in respect of rice, productivity as such has not gone up. This is so in spite of the excellent research that has been taking place in the country. May I know the reason why productivity has not gone up in the country?

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: Though the average rice yield in the country is not upto expectations, recently there have been encouraging trends in regard to productivity. The only difficulty is that there are some imbalances In certain regions it is still low while in certain other regions it is almost upto international levels, though as I said the average is not satisfactory. But next to wheat, it is rice production that is coming up in the country and the view is not as discouraging as the hon. Member thinks.

## सिंचाई सुविधाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता

*109. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :** क्या **कृषि और सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के उपेक्षित और पिछड़े भागों में वर्ष 1976 के अन्त तक सिंचाई सुविधाओं के लिए विश्व बैंक ने कोई परियोजना बना रखी है,

(ख) उस योजना के अन्तर्गत सिंचाई के कितने नए साधन उपलब्ध किये गये है, और

(ग) विशेषकर उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों को उससे क्या लाभ हुआ है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) :** (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

### विवरण

(क) और (ख). विश्व बैंक इस समय आंध्र प्रदेश में पोचम्पाद परियोजना जो राज्य के तेलंगाना क्षेत्र में निजामाबाद और करीमनगर के पिछड़े जिलों के 1 लाख हैक्टेयर क्षेत्र के लिए सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए है और गुजरात में कडाना परियोजना जो खेड़ा जिले में सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने के अतिरिक्त पंचमहल जिले में जो राज्य में गम्भीर रूप से सूखा-प्रभावित और पिछड़ा क्षेत्र है, 13500 हैक्टेयर की सिंचाई होगी के लिए ऋण सहायता दे रहा है।

इस वर्ष के अन्त तक पोचम्पाद में 60,000 हैक्टेयर और पंचमहल जिले में कडाना परियोजना के अन्तर्गत 5,000 हैक्टेयर के लिए सिंचाई शक्यता सृजित हो जाने की सम्भावना है।

उत्तर प्रदेश के लिए विश्वबैंक ऋण सहायता 1973 में प्रारम्भ हुई है जो खेतों पर होने वाले व्यय जैसे चिनाई, कुओं की या खुदाई वाले कुओं के निर्माण, उथले नलकूप, मध्यम गहराई वाले नलकूप, बिजुत और

डीजल के पम्पसेटों को प्रतिष्ठापित करने के लिए वित्त व्यवस्था हेतु है। इस परियोजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के 14 जिले आते हैं जिनमें बलिया, आजमगढ़ और गाजीपुर के पूर्वी जिले शामिल हैं। परियोजना की कुल लागत 72.5 मिलियन डालर (54.3 करोड़ रुपए) है जिसमें विश्व बैंक सहायता 38 मिलियन डालर (28.5 करोड़ रुपए) तक की होगी। विश्व बैंक के दस ऋण सहायता हेतु उनको उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए हमारे देश की उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र इत्यादि में अनेक सिंचाई परियोजनाओं का दौरा कर रहे है।

(ग) भूमि विकास बैंकों और अन्य वाणिज्यिक बैंकों जो उत्तर प्रदेश के लिए विश्व बैंक ऋण परियोजना हेतु वित्तीय एजेंसियां है, ने 30 जून, 1975 तक 15.5 करोड़ रुपए वितरित किए है। इसमें 10,000 चिनाई कुओं, 20,000 उथले नलकूपों और 20,000 मध्यम गहराई वाले नलकूपों का वास्तविक लक्ष्य परिकल्पित है।

उत्तर प्रदेश की शारदा सहायक परियोजना से जो विश्व बैंक के विचाराधीन है रायबरेली, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, बाराबंकी, सुलतानपुर, फैजाबाद, जौनपुर और आजमगढ़ जिलों में लगभग 16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था होगी। चालू वर्ष के अन्त तक इस परियोजना के अन्तर्गत लगभग 3.50 लाख हैक्टेयर सिंचाई शक्यता के सृजित होने की सम्भावना है।

**श्री चन्द्रिका प्रसाद :** माननीय अध्यक्ष जी, वर्ल्ड बैंक का जो उद्देश्य पिछड़े भागों के किसानों की सहायता करने का था, वह लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है क्योंकि इन का इन्ट्रेस्ट साढ़े नौ परसेंट था और अब अप्रैल 1975 से उस को साढ़े दस परसेंट कर दिया है और शैड्यूल्ड बैंक्स जो पिछड़े भागों में मार्जीनल फार्मर्स को लोन दे रहे हैं वह साढ़े चार परसेंट इन्ट्रेस्ट पर दे रहे हैं। तो मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या मन्त्री जी विश्व बैंक से या अपनी तरफ से साढ़े चार परसेंट इन्ट्रेस्ट पर उन को लोन देंगे। यह (क) के बारे में जानना चाहता हूं।

(ख) के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछड़े हुए भागों में जहां पर बैंक लोन दे रहा है, वहां पर मार्जीनल फार्मर्स स्माल फार्मर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसलिए जहां 25 परसेंट सब्सीडी दी जा रही है, उस की सीमा 10 एकड़ तक क्या मन्त्री जी बढ़ाने की कृपा करेंगे।

**श्री केदार नाथ सिंह :** जो वर्ल्ड बैंक से लोन मिलता है वह इन्ट्रेस्ट फ्री लोन होता है लेकिन तीन चौथाई परसेंट सर्विस चार्ज का जोड़ दिया जाता है और यह लोन 50 वर्षों में वापस करने की योजना है। 10 वर्ष ग्रेस के भी मिलते है।

**श्री चन्द्रिका प्रसाद :** हमारा प्रश्न कुछ और था और जवाब कुछ और दिया है। दूसरा प्रश्न यह है कि हर जिले में जो लीड बैंक है उन की मार्फत वर्ल्ड बैंक लोन देता है मार्जीनल फार्मस को लेकिन जो लीड बैंक है उन के पास एजेन्सी नहीं होती है और इस तरह से सब जगह किसानों को पैसा नहीं मिल पाता है। इसलिए मेरा कहना यह है कि उस एरिया में जहां कि लोन दे रहे है, वहां पर जितने भी बैंक है या शाखाएं है, सारा रुपया उन में बांट दिया जाए जिस से किसानों को अधिक से अधिक रुपया मिल सके। क्या ऐसा कोई डाइरेक्टिव मन्त्री जी देंगे ?

**अध्यक्ष महोदय :** यह सवाल तो फाइनेंस से कन्सर्ड है। इसलिए जब फाइनेंस मिनिस्ट्री का सवाल आएगा, उस समय आप पूछिये।

**श्री जगन्नाथ मिश्र :** विश्व बैंक से पिछड़े हुए क्षेत्रों के लिए सिंचाई सुविधायें प्राप्त करने के लिए विश्व बैंक द्वारा क्या क्राइटीरिया

रखा गया है और किस क्राइटीरिया के आधार पर ऐसे क्षेत्रों का चुनाव होता है ?

**श्री केदार नाथ सिंह** . विश्व बैंक की टीम आती है और हमारे देश के जो एक्सपर्टस हैं उन के साथ मिल कर वे एरिया को चुनते है, उस एरिया की क्या सोशो-इकोनौमिक प्राबलेम्स है कितना बैकवर्ड है वहा पर प्राजैक्ट की फीसिबिलिटी क्या है, कितना पैसा लगेगा और जितना लगेगा उसका आउटकम क्या होगा इन सब बातों को देखा जाता है और इसकी बुनियाद पर उसका फैसला किया जाता है।

**श्री नवल किशोर सिंह** विश्व बैंक से सिंचाई कार्यों में तेजी लाने के लिए उन मे वृद्धि लाने के लिए हमारे देश में कर्ज मिल रहे है। सरकार का जो वक्तव्य है इस मे कुछ ही स्थानों का जिक्र आया है लेकिन यह काम सारे देश मे चल रहा है। कई जगह इस तरह का तजुर्बा भी हुआ है कि इस काम में तरह तरह की रुकावटे आ रही है और इस वजह से इसमें जो लक्ष्य है वे पूरे नही हो रहे है ? यदि हा तो क्या सरकार का विचार है कि इन कार्यों का पुनरीक्षण किया जाए ताकि जो लक्ष्य है वे समय के भीतर पूरे हो सके।

**श्री केदार नाथ सिंह** सरकार ने और वर्ल्ड बैंक की जो टीम है उसने इस पर सहमति व्यक्त की है कि उसका एक सैल हमारे यहा सेन्ट्रल वाटर और पावर कमिशन मे हो जो सब मसलों पर विचार करे कि क्या डिले होती है और उसको जल्दी कैसे पूरा किया जा सकता है।

SHRI KARTIK ORAON In the Statement referred to in reply to parts (a) to (c) of Starred Question No 109, it has been stated that the World Bank Teams are visiting several irrigation projects in our country in U P, Orissa, Maharashtra, etc with a view to assess their suitability for credit assistance Here, I want to know whether the word 'etc' includes the State of Bihar with specific reference to Chotanagpur and Santhal Pargana region. This region is the richest area providing 1/3 of mineral wealth of the country and having irrigation potentialities of about 2 percent of cultivable areas and that they are the most backward areas I would like to know as to what are the projects in Bihar that are being financed by the World Bank? What are the guidelines adopted for selecting the projects for the purpose of financing by the World Bank?

SHRI KEDAR NATH SINGH have already mentioned that in Bihar Gandak project has been taken up for being financed by the World Bank But the region which the Hon Member has mentioned, has not been mentioned by the Bihar Government as yet

SHRI THA KIRUTTINAN Sir, recently there was an announcement by the then Tamil Nadu Government that the World Bank had agreed to take up the work of constructing a regulator on the river Vaigai and to modernise the Periar Canal System I would like to know whether this announcement was factual If so what are the details and whether the Government has received any representation from the people of Ramnad District to the effect that this scheme will affect their interests?

SHRI KEDAR NATH SINGH The project mentioned by the Hon Member has not been brought to our notice and no representation has been sent to us in this regard

## New device for storage of foodgrains by Food Corporation

*116 SHRI P GANGADEB Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state

(a) whether the Food Corporation has developed a new and cheaper device for storage of foodgrains,